THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) No charges of corruption were pending against the present Chairman-cum-Managing Director of Hindustan Vegetable Oils Corporation when he was appointed as Chairman-cum-Managing Director.

(b) In view of (a), question does not arise.

Affairs of the barley projects, I.A.R.I. Karnal

2337. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 825 given in the Rajya Sabha on the 2nd May, 1986 and State:

(a) whether the Central Vigilance Commission has since completed the investigation into the complaints against the Project Coordinator, Barley Project, IARI, Karnal;

(b) if so, the details of the findings thereof and the action taken thereon;

(c) if the answer to part (a) above in the negative, whether the Central Vigilance Commission has been requested by the Ministry to expedite the investigation; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) The complaints against Project Coordinator, Barley Project, I.A.R.I. Regional Station, Karnal, have been examined in consultation with the Central Vigilance Commission. As a result of the examination, the Competant Authority has decided to initiate disciplinary proceedings against the Project Coordinator.

(c) and (d) Do not arise.

Nomination of members of Parliament on Telephone Advisory Committees

2338. SHRI PRAMOD MAHAJAN: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that nomination of the Members of Parliament on Telephone Advisory Committees are obtained by Ministry of Communications from the Ministry of Parliamentary Affairs;

(b) if so, what are the guidelines observed by the Ministry of Parliamentary Affairs in sending such nominations; and

(c) what is the number of nominations sent by the Ministry of Parliamentary Affairs during each of the last three years, political partywise and Committee-wise?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) Yes, Sir.

(b) Normally the Members representing/residing in, the geographical jurisdiction of Telephone Advisory Committee are considered on these Committees.

(c) A Statement is laid on the Table of the House. [*See* Appendix CXL. II. Annexure No. 120]

गोल मार्केट, नई दिल्ली में अनधिकृत झुग्गियां

2339. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोल मार्किट, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्टोर (मदर डेरी) के समीप कुछ अनधिकृत झुग्गियां हाल ही में बनायी गयी हैं जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और वहां शांति भंग होने का खतरा है ;

(ख) क्या इन झुग्गियों का निर्माण स्थानीय पुलिस के साथ मिलीभगत से किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन झुग्गियों को हटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सिविया उद्यान मार्ग पर मदर डेरी बूथ के समीप कुछ अनधिकृत झुग्गियां विद्यमान हैं । ये झुग्गियां पी एंड टी पाकेट में हैं । तथापि दूध के बूथ के आस पास मंदिर मार्ग की ओर इस जंक्शन पर हाल ही में कोई झुग्गियां नहीं बनी हैं ।

(ख) और (ग) ये झुग्गियां पुरानी हैं तथा यह पता लगाना बहुत कठिन है कि अनधिकृत झुग्गियां किसकी सहमति से बनी हैं। तथापि, सरकार इन अनधिकृत झुग्गी निवासियों को बेदखल करने के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है । इस प्रयोजनार्थ, अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिये गये हैं ।

अखिल भारतीय मेयर परिषद् का सम्मेलन

2340. **श्रीमती रेणुका चौधरी** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय मेयर परिषद् के 23वें वार्षिक सम्मेलन में व्यक्त किये गये इस आशय के विचारों की जानकारी है कि देश के बड़े बड़े नगरों की उपेक्षा की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि शहरी समस्याओं के समाधान हेतु कई आयोगों का गठन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो किस किस आयोग के प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं और उनमें से कौन कौन सी सिफारिश लागू की गयी हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) से (घ) अक्तूबर, 1986 में हुई स्थानीय शासन और शहरी विकास के लिये केन्द्रीय परिषद् की 23वीं बैठक और केन्द्रीय परिषद तथा अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारी समिति की 12वीं संयुक्त बैठक में नोट किया कि शहरों में तीव्रता से बढ़ रही शहरी मलिन बस्तियों की जटिल समस्या सहित शहरी विकास के विभिन्न पहलुओं से संबंधित व्यापक सिफारिशें देने हेतु भारत सरकार ने एक उच्चाधिकार प्राप्त राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग नियुक्त किया था । पालिका निकायों को प्रशासनिक रूप से लाभप्रद और वित्तीय रूप से आत्म निर्भर बनाने की समिति ने अनेक सिफारिशें भी की हैं । ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और वह उनके कार्यान्वियन के लिये उपयुक्त कार्यवाही कर रहा है ।

राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने अपनी प्रथम अंतरिम रिपोर्ट जनवरी, 1987 में दे दी है जिसकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है । इस विषय पर सरकार द्वारा कोई अन्य आयोग गठित नहीं किया गया है ।

गारलैण्ड केनाल योजना

2341. **श्रीमती रेणुका चौधरी** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में नदियों के अतिरिक्त पानी को सूखे क्षेत्रों में ले जाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं तैयार की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से प्रमुख कौन-कौन सी हैं और क्या इनमें से एक ऐसी योजना "गारलैण्ड केनाल योजना" थी ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना को सब से पहले कब तैयार किया गया था ; और

(घ) इस योजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?